साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 7, अंक : 39 (प्रति बुधवार), इन्दौर 18 मई 2022 से 24 मई 2022 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

भूपेंद्र यादव ने मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया

नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय दल मरुस्थलीकरण के 15वें सम्मेलन (UNCCD COP15) के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आबिदजान, कोटे डी आइवर पहुंचे। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों के सम्मेलन का चौदहवां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और भारत संगठन का वर्तमान अध्यक्ष है।

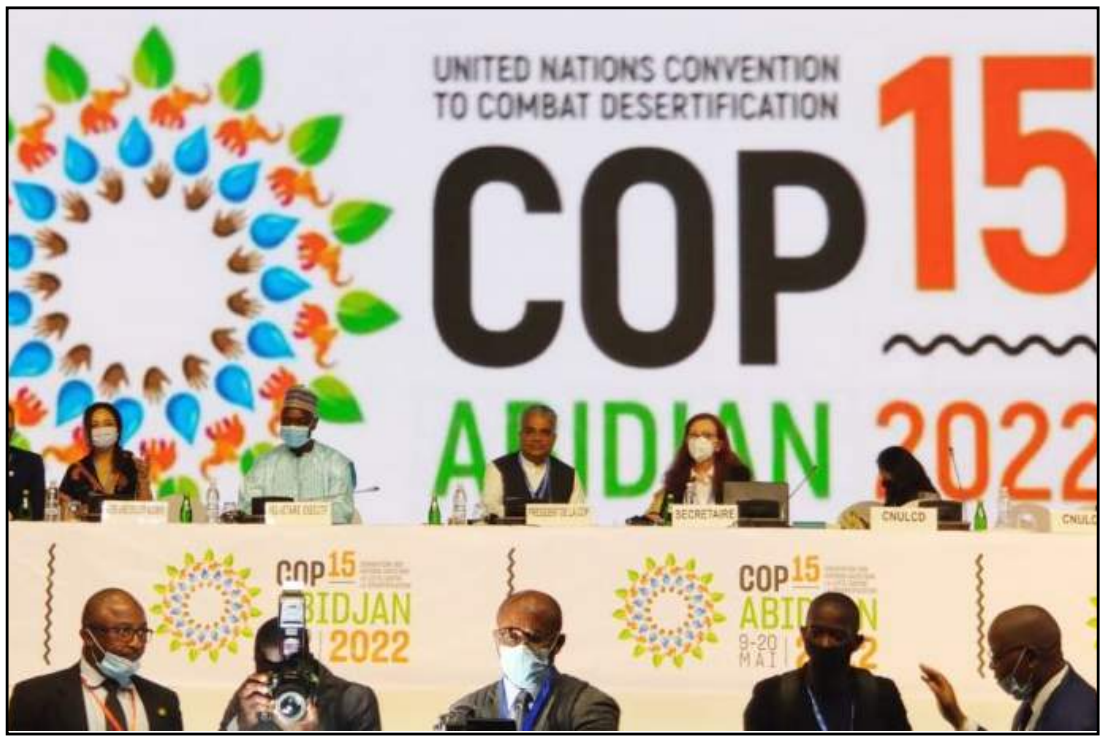

कोविड के प्रकोप के बावजूद, भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान भूमि क्षरण को रोकने और उलटने के वैश्विक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों को एक साथ लाने में प्रमुख योगदान दिया। भारत की अध्यक्षता के दौरान, G-20 नेताओं ने भूमि क्षरण का मुकाबला करने और नए कार्बन सिंक विकसित करने के महत्व को पहचानते हुए, 2030 तक सामूहिक रूप से 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, अन्य देशों से इस वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त20 के साथ सेना में शामिल होने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) के पार्टियों के सम्मेलन (COP15) का पंद्रहवां सत्र, जो आबिदजान, कोटे डी आइवर में होगा, जो सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और दुनिया भर के अन्य प्रमुख हितधारकों के नेताओं को एक साथ लाएगा ताकि भविष्य में स्थायी भूमि प्रबंधन में प्रगति हो सके और भूमि और अन्य प्रमुख स्थिरता मुद्दों के बीच संबंधों का पता लगाया जा सके। इन समस्याओं पर उच्च-स्तरीय चरण में विचार किया जाएगा और इसमें राष्ट्राध्यक्षों की शिखर बैठक, उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन और संवादात्मक संवाद सत्र के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त विशेष और साइड गतिविधियाँ शामिल होंगी। सूखा, भूमि की बहाली, और भूमि अधिकार, लैंगिक समानता और युवा सशक्तिकरण सहित संबद्ध समर्थक सम्मेलन की प्रमुख प्राथमिकताओं में से हैं। COP15 से NCCD की 197 पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तावों के माध्यम से भूमि की बहाली और सूखे से निपटने के लिए स्थायी समाधान तैयार करने की उम्मीद है, जिसमें भविष्य के प्रूफिंग भूमि उपयोग पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा।

फूड फॉरेस्ट से सुधरेगी किसानों और पर्यावरण की सेहत

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार फूड फॉरेस्ट विकसित कर हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण की पहल करने जा रही है. इसके लिए सरकार ने अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों (एग्रो क्लाइमेटटिक जोन) के 15 जिलों को चिन्हित किया है. इन जिलों में स्थानीय किसानों के सहयोग से अगले छह माह में फूड फारेस्ट विकसित किए जाएंगे. इससे पर्यावरण और किसानों दोनों की सेहत सुधरेगी. जो जिले इसके लिए चिन्हित किए गए हैं उनमें बिजनोर, अमरोहा और सहारनपुर आम की पट्टी के संभल, रामपुर, बदायूं अमरूद पट्टी के हैं. इसी तरह अन्य जिले भी किसी न किसी फलपट्टी में शामिल हैं. ये पार्क इको फ्रेंडली होने के साथ खुद में कृषि विविधीकरण की भी मिसाल होंगे. फूड फारेस्ट में संबंधित क्षेत्र के कृषि जलवायु क्षेत्र (एग्रो क्लामेटिक जोन) के अनुसार पौधों का चयन किया जाएगा.

प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए फूड फारेस्ट में दलहनी फसलों को भी स्थान दिया जाएगा. मसलन गोरखपुर में विकसित किए जाने वाले फूड फारेस्ट में पहले चरण में आम, अमरूद, अनार और पपीते के पौध लगाये जाएंगे. दूसरे चक्र में जामुन, बेर यानी छोटे जंगली फलों के पौधे लगाए जाएंगे. तीसरे चक्र में अरहर, मूंग, उड़द, मटर व चने की बोआई होगी. चौथे चरण में लेमनग्रास, तुलसी, अश्वगंधा जैसे हर्बल प्लांट पार्क लगेंगे. पांचवें चक्र में गिलोय, अंगूर, दमबूटी आदि बेल प्रजाति रोपित होगी. इसी तरह पौधों का चयन अलग-कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार होगा. इसमें लगी दलहनी फसलें प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण (फिक्सेशन) का काम करेंगी. पक्षियों की बीट प्राकृतिक खाद का काम करेगी. फूलों पर आने वाली मधुमक्खियां और तितलियां परागण का काम करेंगी. दरअसल सरकार का मकसद किसानों की आय बढ़ाना है. धान-गेंहू की परंपरागत खेती की बजाय कृषि विविधीकरण से ही ऐसा संभव है. ये पार्क खुद में इसकी नजीर होंगे. यही नहीं इन पार्कों से प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भविष्य में कच्चा माल मिलेगा. फलदार पौधों का रकबे के साथ हरियाली भी बढ़ेगी. फूड फारेस्ट में बुलन्दशहर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनोर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत,गोरखपुर और गौतमबुद्धनगर शामिल किया गया है. वन पर्यावरण मंत्री अरूण सक्सेना ने कहा कि फूड फॉरेस्ट के जरिए किसानों और पर्यावरण दोनों की सेहत में सुधार होगा. फल वाले वृक्ष लगाने से किसानों की आय भी बढ़ेगी. जुलाई से पौधारोपण का कार्य भी शुरू हो जाएगा. यह प्रदेशवासियों के लिए बेहद रोचक होगा. इस वन में इंसान से लेकर पशु-पक्षियों के भोजन की श्रृंखला तैयार की जाएगी.

पर्यावरण संरक्षण को आचरण में लाने की जरूरत

नई दिल्ली पर्यावरण संरक्षण को हर व्यक्ति को आचरण में लाने की जरूरत है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को साफ-सुथरी हवा, स्वच्छ नदियां और उज्ज्वल भविष्य तभी दे पाएंगे जब पर्यावरण बचेगा। पर्यावरण प्रदूषण के कारण बच्चों में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। ये बातें राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक व प्रख्यात विचारक केएन गोविंदाचार्य ने कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में कहीं। वे राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के 18वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

गोविंदाचार्य ने कहा कि व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा समाज होता है। समाज के प्रति सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए अच्छे नागरिक बनना जरूरी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह ने कहा जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन तक 18 साल बीतने के बाद भी लोगों की पहुंच नहीं बन पाई है। इसका बड़ा कारण है लोगों में सामाजिकता की कमी। आजकल के युवा पढ़-लिख कर बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरी पाना और फिर उसी नौकरी को अपना सब कुछ समझ कर लगे रहना ही अपना सबसे पहला काम समझ रहे हैं। उन्हें दुनिया और समाज से लेना-देना नहीं है। इस दौरान आंदोलन से जुड़े कई वक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में आंदोलन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री वसवराज पाटिल ने सभी का आभार जताया। इस दौरान नदी संवाद सहित अन्य आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई।

नेक पहल : सरकारी स्कूल देंगे पर्यावरण संरक्षण का संदेश

वाराणसी जिला दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक वायु प्रदूषण है। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद से संबद्ध स्कूलों ने जिले को प्रदूषण मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत हर स्कूल में बगीचा होगा। छात्र-छात्राएं पौधे रोपेंगे जबकि हर हर शिक्षक एक-एक पौधे को गोद लेंगे। साथ ही स्कूलों में भू- जल संचयन का भी इंतजाम किया जाएगा।

बेसिक स्कूलों में जहां एक ओर विद्यार्थी पौधरोपण करेंगे वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग हर स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएगा। इसके पीछे सोच वर्षा जल का संचयन कर भू-जल के गिरते स्तर को मेंटेन करना है। लिहाजा स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ सोख्ता भी बनाया जाएगा जिससे वर्षा का जल जमीन के भीतर जा सके। स्कूलों में फलदार और औषधीय गुण वाले पौधे लगाए जाएंगे। इसमें भी आंवला, केला, सहजन, नीबू आदि का पौधा जरूर रोपा जाएगा। इसके अलावा हर स्कूल में न्यूटी गार्डन बनाने को कहा गया है। इसके तहत ही फलदार व औषधीय गुणों वाले पौधों के साथ सब्जियां भी उगाई जाएंगी। कहा गया है कि बच्चे स्कूलों में पौधे लगाएंगे तो इससे उनके भीतर पर्यावरण के प्रति लगाव पैदा होगा जिससे वो अभिभावको संग आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकेंगे। ÷बच्चों संग शिक्षक भी पौधरोपण करेंगे और अपने द्वारा लगाए गए पौधे को गोद लेंगे,ताकि उनका संरक्षण हो सके। इससे स्कूलों में हरियाली आएगी। साथ ही बच्चों में प्रकृति से लगाव होगा। उनमें बागवानी की प्रवृत्ति विकसित होगी।

स्कूलों से निकले वाला कचरा और गंदा पानी होगा रीसाइकल

सोलन। जिले के स्कूलों में अध्यापकों और विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रशिक्षित किया जाएगा। स्कूलों में सूखा, गीला कचरा और गंदे पानी को दोबारा प्रयोग किया जाएगा। शिक्षा विभाग और एक निजी संस्था अर्थजस्ट अध्यापकों और विद्यार्थियों को इसकी जानकारी देगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहतरीन कार्य करने वाले स्कूलों को राष्ट्र स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। स्कूलों में विद्यार्थियों को हाथ धोने के बाद व्यर्थ बह रहे पानी का दोबारा प्रयोग सिखाया जाएगा। सूखे और गीले कचरे से खाद बनाने की भी जानकारी दी जाएगी। संस्था के समन्वयक आशीष और श्रेय गुप्ता ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की मुहिम के तहत पहले अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद अध्यापक बच्चों को इसकी जानकारी देंगे। इसमें कचरे को खुले में न फेंककर उसका खाद और सजावटी सामान के लिए किया जाएगा। हाथ धोने के बाद व्यर्थ गिरने वाले पानी को एकत्र कर उसका प्रयोग पौधों की सिंचाई समेत शौचालय के प्रयोग में किया जा सकेगा। जून माह से इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। इस संबंध में स्कूलों की प्रतियोगिताएं भी होंगी। बेहतरीन स्कूलों को सम्मानित भी किया जाएगा। जिला विज्ञान समन्वयक अमरीश शर्मा ने बताया कि निजी संस्था के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण की पहल की है। इसमें बच्चों के साथ शिक्षकों को भी जोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी ऐसे कार्यक्रमों में सोलन के दो निजी स्कूलों को राष्ट्र स्तर पर सम्मान मिला है।

पक्षियों को बचाएंगे तो ही बचेगा पर्यावरण

कपूरथला पुष्पा गुजराल साइंस सिटी की ओर से अंतरराष्ट्रीय पक्षी प्रवास दिवस पर पक्षी संसार को आपस में जोड़ते है विषय पर वेबिनार करवाया गया। वेबिनार में प्रदेश के अलग-अलग शैक्षिक संस्थानों से 100 के करीब विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने भाग लिया।

वेबिनार में जी भारतीय जंगली जीव इंस्टीट्यूट देहरादून के सलाहकार व विज्ञानी डा. बितापी सी सिन्हा मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित हुए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि विश्व पक्षी प्रवास दिवस प्रवासी पक्षियों की दरपेश खतरों, उनके हमारे पर्यावरण में महत्व, देखभाल व अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए एक प्रभावशाली साधन है। उन्होंने बताया कि उप-महादीप गर्मियों व सर्दियों में प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करता है। एक अनुमान के मुताबिक पक्षियों की सैंकड़ों प्रजातियां कड़ाके की ठंड से बचने के लिए मैदानी क्षेत्र की तलाश में भारत की तरफ उड़ती है। कुदरती वातावरण के साथ पक्षियों की सुंदरता कुदरत के प्रेमियों के लिए अलग नजारा पेश करती है। साइंस सिटी की डायरेक्टर जनरल डा.नीलमा जेरथ ने कहा कि पक्षी कुदरत के दूत है और इसलिए इनके रख रखाव के साथ-साथ इनके रैन बसेरा को संभालना बहुत जरुरी है। जंगली जीवों की पनाहगाहों व जलगाहें पक्षियों के अस्थायी रहन बसेरे है। इसलिए इनकी सुरक्षा को यकीनी बनाना है। उन्होंने बताया कि रामसर साइट के अधीन आती पंजाब की छह अंतरराष्ट्रीय स्तर की जलगाहें सर्दी व गर्मी में प्रवासी पक्षियों के लिए रैन बसेरों के तौर पर पूरी दुनिया में जानी जाती है। लगभग आधी दुनिया के पक्षी मौसमी स्थिति से बचने के लिए इन जलगाहों की तरफ उड़ान भरती है। उन्होंने कहा कि तरनतारन जिले की हरिके जलगाह उत्तर

भारत की सबसे बड़ी जलगाह है। आर्कटिक, साइबेरिया, चीन, मंगोलिया व ऊपरी हिमालय से बड़ी संख्या में हर साल प्रवासी पक्षी जहां आते है। हरिके में युरेशियन क्रट, ग्रेलैग गोस (हंस), बार हैडगडवाल व उत्तरी सोवेलर महत्वपूर्ण पक्षियों का तांता लगा रहता है। यहां बने जंगली जीवों के रैन बसेरे भी इन जीवों के स्थायी निवास के तौर पर काम आते है। इन जलगाहों की सुरक्षा बहुत जरुरी है।

जीवन और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पूरक

एमआईटी ढालवाला में एक दिवसीय पर्यावरण संरक्षण जागरूकता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. भावुतोष शर्मा वैज्ञानिक उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं शोध केंद्र देहरादून और हेमंत गुप्ता थे। संस्थान निदेशक रवि जुयाल ने कहा कि जीवन और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दूषित पर्यावरण में स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में पर्यावरण को स्वच्छ करने की जितनी आवश्यकता है इतनी इसे पूर्व कभी नहीं रही। यदि हम अभी भी नहीं चेते तो परिस्थितियां अत्यंत भयावह हो सकती है। डॉ. भावतोष शर्मा और हेमंत गुप्ता ने तथ्यों और आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पर्यावरण और उसके संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं को छात्रों के समक्ष रखा।

उत्तराखंड के जंगलों में हाथी की लीद में मिले प्लास्टिक के अंश, बड़े खतरे के संकेत

उत्तराखंड। दुनिया भर के लिए प्लास्टिक अब एक बड़े खतरे में बदल चुका है। आज दुनिया की शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो इससे अछूती हो। हिमालय के ऊंचे शिखरों से समुद्र की अथाह गहराइयों तक में इसके पाए जाने के सबूत मिले हैं। जो दर्शाता है कि यह खतरा पर्यावरण पर किस तरह हावी हो चुका है। लेकिन अब इंसानों और जीवों के शरीर में इसके अंश का मिलना बड़े खतरे की ओर इशारा करता है।

अब तक आपने गाय और अन्य जानवरों द्वारा प्लास्टिक को निगलने और उनके शरीर में इसके अंश के मिलने की बात तो सुनी होगी पर हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में वैज्ञानिकों को एशियाई हाथी (एलिफस मैक्सिमस इंडिकस) की लीद में प्लास्टिक के अंश मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि आज प्लास्टिक न केवल शहरों में बल्कि उससे दूर जंगलों में रहने वाले जीवों के शरीर में भी अपनी पैठ बना चुका है। भारतीय शोधकर्ताओं ने इसपर एक व्यापक अध्ययन किया है जिसके नतीजे जर्नल फॉर नेचर कंजर्वेशन में प्रकाशित हुए हैं। गौरतलब है कि 'एलिफस मैक्सिमस इंडिकस' एशियाई हाथी की चार उपजातियों में से एक है, जिस भारतीय हाथी भी कहा जाता है। हाथी की यह प्रजाति 6 से 11 फ़ीट ऊंची होती है। वजन करीब 5,000 किलोग्राम होता है। आज दुनिया में इस प्रजाति के केवल 20 से 25 हजार हाथी ही बचे हैं। यही वजह है कि इसे संकटग्रस्त प्रजाति की लिस्ट में शामिल किया गया है। हाथी की लीद में मिले प्लास्टिक और अन्य कचरे की जांच के लिए शोधकर्ताओं ने उनके आहार की जांच की है और पाया है कि उत्तराखंड के जंगलों और उसके किनारों से एकत्र किए लीद के नमूनों में प्लास्टिक के साथ अन्य तरह के इंसानी कचरे के अंश मिले हैं, जिसकी मात्रा के निर्धारण के लिए उन्होंने इस कचरे की पहचान की है और वर्गीकृत किया है साथ ही उन्हें मापा भी है।

32 फीसदी नमूनों में मिले इंसानी कचरे के अंश- वैज्ञानिकों को अपनी जांच से पता चला है कि एकत्र किए गए लीद के करीब एक तिहाई (32 फीसदी) नमूनों में इंसानी कचरे की उपस्थिति के सबूत मिले हैं। वहीं जिन 32 फीसदी नमूनों में इंसानी कचरे के अंश मिले हैं उनमें से 85 फीसदी में प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं जिनका आकार 1 से 355 मिलीमीटर के बीच था। मतलब की हर नमूने में प्लास्टिक के करीब 47 कण मिले हैं। वैज्ञानिकों को यह जानकर हैरानी हुई की जहां जंगलों के किनारे से लिए नमूनों में प्रति 100 ग्राम नमूनों में प्लास्टिक के 35.34 कण मिले हैं वहीं घने जंगलों में यह आंकड़ा बढ़कर दोगुना हो गया था। जहां प्रति 100 ग्राम लीद में प्लास्टिक के 85.3 कण पाए गए हैं। इसके साथ ही जंगलों के अंदर से लिए प्रति 100 ग्राम नमूने में अन्य नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कांच, धातु, रबर बैंड, मिट्टी के बर्तन और टाइल के टुकड़ों के 34.79 कण मिले हैं, जबकि जंगल के किनारों से लिए नमूनों में केवल 9.44 कण प्रति 100 ग्राम में पाए गए हैं।

देर होने से पहले उठाने होंगे ठोस कदम- इसी तरह कोयंबटूर वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट (सीडब्ल्यूसीटी) के सदस्यों को कोयंबटूर में मरुथमलाई के पास जंगली हाथी की लीद में सैनिटरी नैपकिन, मास्क और प्लास्टिक बैग सहित अपशिष्ट पदार्थ मिले थे। जीवों पर प्लास्टिक के प्रभावों का एक ऐसा ही सबूत कावेरी नदी से भी मिला था, वैज्ञानिकों के मुताबिक कावेरी नदी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक जैसे प्रदूषक मछलियों के कंकाल में विकृति पैदा कर रहे हैं। साथ ही बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के चलते इनके विकास पर भी असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले जर्नल ऑफ थ्रैटेनेड टैक्सा में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में उत्तराखंड में संरक्षित क्षेत्रों के पास खुले में कचरे को डंप करने से पैदा होने वाले खतरे को लेकर आगाह किया था। शोध के मुताबिक यह ओपन डंप शिवालिक हाथी अभ्यारण्य में एशियाई हाथियों के लिए एक उभरता हुआ खतरा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक हाथी की लीद में माइक्रोप्लास्टिक की तुलना में मैक्रोप्लास्टिक के ज्यादा अंश मिले हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो यह पहला अध्ययन है जो एशियाई हाथी द्वारा प्लास्टिक और अन्य तरह के कचरे को निगले जाने की पुष्टि करता है। साथ ही यह हमारे गैर-जिम्मेदाराना तरीके से प्लास्टिक के इस्तेमाल और ठोस कचरे के प्रबंधन से जुड़ी नीतियों पर भी सवाल खड़ा करता है। वनजीवों के शरीर में प्लास्टिक की मौजूदगी एक बड़ा खतरा है जो पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में यह जरुरी है कि इन जीवों के आवास के आसपास प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे को कम करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी कारगर रणनीति तैयार की जाए।

यूपी के इन 13 शहरों में बनेंगे 26 सिटी फारेस्ट, सुरक्षित होगा पर्यावरण

लखनऊ शहर में रहने वालों को अब सुरक्षित पर्यावरण मिल सकेगा। सरकार ने यूपी के 13 शहरों में 26 सिटी फॉरेस्ट बनाकर इसे साकार करने की कोशिशें तेज कर दी है। इस योजना को अगले छह महीने में विकसित कर लिया जायेगा। जिन शहरों को चिह्नित किया गया है, उनमें न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है।

इसके अलावा आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, कानपुर, औरैया, हरदोई, हाथरस, इटावा, रायबरेली, मुरादाबाद और अमरोहा में भी फॉरेस्ट सिटी बनाए जाने की योजना है। इन शहरों में फॉरेस्ट तैयार होने पर पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी नेचुरल पिकनिक स्पॉट का विकल्प मिलेगा। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार, इससे इको टूरिज्म के दायरे का भी विस्तार होगा। स्थानीय स्तर पर रोजी-रोटी के अवसर मिलना इस अभिनव योजना का बोनस होगा। नगर वन के लिए केंद्र की ओर से निधारित 2 करोड़ की धनराशि में से 1.40 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार को जारी कर दी गई है। जल्द ही यह धनराशि संबंधित जिलो में काम शुरू कराने को उपलब्ध करा दी जाएगी।विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर इस बाबत पौधरोपण की शुरूआत भी हो सकती है। नगर वन में बनेंगे स्मृति वन, आरोग्य और नक्षत्र, वाटिकायें वन क्षेत्र बाउंड्री या बाड़ से घिरे होंगे। इनमें स्मृति वन, आरोग्य वाटिका, नक्षत्र वाटिका और हरिशंकरी वाटिका बनाई जाएगी। जैव-विविधता के लिए इसमें सभी प्रकार की सजावटी, झाड़ियां, बेलदार, औषधीय पौधे, फूल और फलों के पौधे लगाए जाएंगे। यहां एडवेंचर स्पोर्ट्स, साइकिल ट्रेक, पाथवेज, आपेन जिम, जागर्स पार्क, बेंच समेत जनसुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर डॉ. वेंकटेश दत्ता बताते हैं कि धीरे-धीरे जंगल समाप्त हो गये।अगर यूपी की बात करें तो यहां पर सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, शाहजहांपुर, पीलीभीत में पहले प्राकृतिक जंगल थे। पलाश के वन थे। लकड़ियों के अंधाधुंध कटाई से यह कम हो गए। प्राकृतिक जंगल में पौधे खुद अपने आप आते हैं। इसमें जलवायु के अनुकूल वाली प्रजातियां आ जाती हैं। शहरों के जंगल की योजना में प्राकृतिक जंगल बनाया जाए। सिटी फारेस्ट का जो कांसेप्ट है उसका

उद्देश्य है कि शहरों में फारेस्ट के पैचेज हो। जो जगह बची है उसमें प्राकृतिक जंगल बनाया जाय। इसके लिए कुछ तरकीब है। जापान के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे अकीरा मियावाकी उन्होंने मियावाकी फॉरेस्ट का कांसेप्ट दिया। जो भारत में अब प्रचलित हुआ है। इसमें कम एरिया में अधिक घनत्व वाले छायादार पौधे प्राकृतिक जंगल तैयार किया जाता है। सिटी फारेस्ट बहुत अच्छा विकल्प है भविष्य में यही जंगल होंगे। सिटी के फेफड़ो को सुरक्षित रखेंगे। शहरों को जलवायु परिवर्तन से बचाएंगे। सूक्ष्म जलवायु को रेग्युलेट करेंगे। तापमान ठीक रहेगा। जंगल बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना बताया कि 26 जिलों में फॉरेस्ट सिटी बनाने की योजना है। इसमें अधिक छायादार वाले वृक्ष लगाए जाएंगे। राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। धार्मिक स्थल में पेड़ लगाए जाने पर ज्यादा जोर है क्योंकि यहां पर पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। खाली जगहों में नगर वन वाटिकाएं बनाएं जाने की योजना है। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण मुख्यमंत्री योगी की प्राथमिकताओं में से एक है। अपने पहले कार्यकाल से ही उनका जोर प्रदेश में हरियाली का रकबा बढ़ाने का रहा है। लोग इस अभियान से अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें इसके लिए मुख्यमंत्री की पहल पर गंगा के किनारे गंगा वन, नक्षत्र वाटिका, गृह वाटिका, राम वनगमन मार्ग पर उस समय के पौधों का पौधरोपण, विरासत वृक्षों का संरक्षण एवं संवर्धन, ब्रज क्षेत्र में द्वापर युग मे जितने तरह के वनों का जिक्र है उनको केंद्र में रखकर पौधरोपण, अपने पूर्वजों के नाम पर पौधरोपण जैसी योजनाएं शुरू की गयीं।

मध्यप्रदेश में 16 लाख से अधिक वृक्षों का हुआ कत्लेआम, पर्यावरण परिस्थिति को स्पष्ट करने श्वेत पत्र लाए सरकार

जबलपुर। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौरान सांस व आक्सीजन महत्वपूर्ण रही है, पूरी दुनिया ने ये भयावह दृश्य देखा था। इसके बावजूद जिन पेड़ों से हमें आक्सीजन प्राप्त होती है, उन जीवनदायनी पेड़ों को बचाने की दिशा में ठोस प्रयास नहीं हुआ।

इन्हें बचाने कोई मास्टरप्लान नहीं है, अपितु खुद सरकार ही विकास के नाम पर इनकी बलि चढ़ाने पर आमादा है। यह बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकास के नाम पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष 2020 में 16 लाख से अधिक पेड़ काट दिए और प्रतिपूरक वृक्षारोपण में भी कोताही बरती गई। नागरिक उपभोक्ता मंच ने मध्य प्रदेश सरकार पर विकास के नाम पर पर्यावरण के विनाश का आरोप लगाते हुए बताया कि दिल्ली में भी विकास किया गया परंतु एक भी वृक्ष नहीं काटा गया अपितु 50 हजार पौधों का रोपण किया गया।लिहाजा, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के पर्यावरण परिस्थिति को स्पष्ट करने श्वेत पत्र लेकर आए।

वृक्ष काटने में मध्यप्रदेश अव्वल - मनीष शर्मा प्रांतीय संयोजक नागरिक उपभोक्ता मंच ने बताया कि लोकसभा के वर्तमान सत्र में स्वयं पर्यावरण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री द्वारा जानकारी प्रस्तुत की है, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2020-21 में मध्यप्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं एवं संरचनाओं के निर्माण हेतु 1640532 वृक्षों को काटा गया।यह पूरे देश में सर्वाधिक है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 30 लाख 95 हजार वृक्षों को काटा गया है। आंकड़े स्पष्ट कहते हैं संपूर्ण देश में काटे गए वृक्षों में आधे से अधिक मध्यप्रदेश में काटे गए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दुगने वृक्ष लगाने का दावा किया गया परंतु उत्तरजीविता संबंधी कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की। वहीं प्रतिपूरक वृक्षारोपण में मात्र 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मनीष शर्मा ने बताया की सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी के सुझाव को माने तो काटे गए वृक्षों की कीमत खरबों रुपए हो सकती है। कमेटी के अनुसार वृक्ष की आयु तथा अगले 25 वर्षों में उसके द्वारा दी जाने वाली आक्सीजन की कीमत के आधार पर एक-एक वृक्ष की कीमत पांच लाख तक मानी की जा सकती है। श्वेत पत्र लाए सरकार- नागरिक उपभोक्ता मंच के प्रफुल्ल सक्सेना, सुधीर घरे, सुभाष चंद्र, मधुबाला श्रीवास्तव, आश्रिता पाठक, पवन कौरव, सज्जाद अली, अरविंद स्थापक, अभिषेक मेहरा, इमरान खान, शिवकुमार आदि ने मध्यप्रदेश सरकार को पत्र के माध्यम से यह मांग की है कि प्रदेश के बिगड़ते पर्यावरण व प्रदेश में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव को स्पष्ट करने हेतु श्वेतपत्र लेकर आए ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके।

जलवायु परिवर्तन- पर्यावरण मंत्री बोले- विकासशील देश मिलकर करें काम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जरूरी

नई दिल्ली केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कहा कि विकासशील देशों द्वारा जलवायु कार्यों का महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अन्य सहायता के पर्याप्त वितरण पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन पर ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेते हुए मंत्री ने जलवायु परिवर्तन से संयुक्त रूप से निपटने, कम कार्बन की दिशा में तेजी लाने के लिए दृष्टिकोण तलाशने की जरूरत पर जोर दिया।

ब्रिक्स उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता चीन के पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री हुआंग रनकिउ ने की और इसमें ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने भाग लिया। यादव ने मजबूत जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसमें सावधानीपूर्वक खपत और कचरे में कमी के आधार पर स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अक्षय ऊर्जा, स्थायी आवास, अतिरिक्त वन और वृक्षों के माध्यम से कार्बन सिंक के निर्माण, स्थायी परिवहन की तरफ शिफ्ट होने, ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में कई मजबूत कदम उठाकर मिसाल कायम कर रहा है। यादव ने जिक्र किया कि कैसे भारत ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को उत्तरोत्तर कम करना जारी रखा है।

सूखते पौधों के अब पर्यावरण प्रेमी बन रहे हैं सहारा

आष्टा। शहर के कन्नौद रोड, तहसील कार्यालय, कृषि उपज मंडी एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्राउंड तक सड़क के दोनों किनारे पर ग्रीन बेल्ट सहित अन्य स्थानों पर ग्रीन बेल्ट का बनाए। जहां पर्यावरण संस्था के पदाधिकारियों, नपा व प्रशासन ने बारिश के बाद पौधरोपण किया था। ताकि हरियाली को बढ़ावा मिल सके। यहां रोपे गए पौधे भीषण गर्मी में पानी के अभाव में मुरझा रहे हैं। पर्यावरण संस्था के पदाधिकारी दूर-दूर से पानी लाकर पौधों को सींच रहे। नगर पालिका परिषद द्वारा ग्रीन बेल्ट में पानी की व्यवस्था नहीं की। इसके कारण ग्रीन बेल्ट में हरियाली दम तोड़ रही है।

पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि शहर की सुंदरता व हरियाली के लिए ग्रीन बेल्ट व बगीचों में प्रशासन, नपा व सामाजिक संस्थाओं द्वारा पौधरोपण किया था। पर्यावरण संस्था के पदाधिकारी ग्रीन बेल्ट की जमीन पर रोपे गए पौधों की देखभाल कर रहे हैं। भीषण गर्मी में पौधे झुलस रहे। इन्हें पानी की आवश्यकता है। लेकिन नगर पालिका इन पौधों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं की। संस्था के पदाधिकारी व समाजसेवी संस्थाओं के सदस्य प्लास्टिक की कैनों में दूर-दूर से पानी भरकर लाकर पौधों को पिला रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने नपा प्रशासक एसडीएम आनंद सिंह रजावत, सीएमओ नंदकिशोर पारसनिया से मांग की है कि ग्रीन बेल्ट के पौधों पर ध्यान दें और यहां पानी की व्यवस्था करें ताकि संस्था के पदाधिकारी प्रतिदिन सुबह में सेवा करने के दौरान पेड़-पौधों को पानी पिला सके। कृषि उपज मंडी कार्यालय, मंडी के सामने का पार्क रोड के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट, नगर में ग्रीन बेल्ट बनाकर यहां पौधरोपण किया। सामाजिक संस्थाओं द्वारा सप्ताह में एक दिन ग्रीन बेल्ट की जमीन पर श्रमदान कर पेड़-पौधों का रखरखाव किया जाता है। संस्था के पदाधिकारी पूर्व पार्षद पंकज यादव कुशल पाल लाला प्रतिदिन हाथों में पानी की कैन लेकर इन्हें सींचने पहुंचते हैं। ग्रीन बेल्ट में पानी के लिए नपा द्वारा नल कनेक्शन नहीं करने के कारण संस्था के पदाधिकारियों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन रात के समय शहर की प्रमुख सड़कों को पानी से धोया जाता था। ताकि सर्वे में अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। इस बार डेम, तालाब में पर्याप्त पानी होने के बावजूद नगर पालिका द्वारा ग्रीन बेल्ट की अनदेखी की जा रही है। यहां पेड़-पौधे गर्मी के कारण सूख रहे हैं। नपा से शहर के सभी ग्रीन बेल्ट व बगीचों में लगे पेड़-पौधों में टैंकरों से पानी पिलाने की मांग की है। ताकि यह छोटे पौधे पेड़ बनकर गर्मी में

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008